

कि सरकार बदली है, इस लिये मैं पहले के आश्वासन से बंधा हुआ नहीं हूँ ।

DR. S. CHANDRASEKHAR : As I have said earlier, a number of Ambassadors and leaders of delegations from the South East Asian region met me and.....

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं सीलोन के बारे में पूछ रहा हूँ ।

DR. S. CHANDRASEKHAR : pressed their claims, mentioning the merits of their candidates. I was bound to tell them that I am bound by the directive of the Government of India since I am a government representative.

MR. SPEAKER : The question of the hon. Member is whether the Ceylon representative referred to the assurance given by the previous Minister.

DR. S. CHANDRASEKHAR : I am not aware of any such private conversation. I do not record them.

श्री राम सेवक यादव : कैसा साफ झूठ बोला गया है !

विदेशों से सहायता

+

* 512. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री रामावतार शर्मा :

श्री शिवकुमार शास्त्री :

महंत दिग्विजय नाथ :

डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धीरे-धीरे विदेशी सहायता की राशि को कम करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जैसा कि 'तीसरी पंचवर्षीय आयोजना' में बताया गया था, आर्थिक आयोजना का एक

मुख्य उद्देश्य यह था कि विदेशी सहायता पर निर्भर रहने को धीरे-धीरे कम करके आत्म निर्भरता प्राप्त की जाये । आयोजना का ही एक उद्देश्य होने के कारण इसे ऐसा स्वतन्त्र प्रस्ताव नहीं समझा जा सकता जिसके बारे में अलग से निश्चय करने की आवश्यकता हो ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूँ कि अब तक पिछली तीन पंच वर्षीय योजनाओं में अथवा दूसरे विकास कार्यक्रमों में भी भारत ने जो विदेशों से सहायता ली है, अथवा कम्पनियों में समझौते के रूप में जो विदेशों का धन भारत में लगा हुआ है, उस की कुल मात्रा कितनी है और उसके सूद के रूप में भारत को प्रतिवर्ष कितना देना पड़ता है ?

श्री मोरारजी देसाई : तीसरे प्लान में अब तक जो मिला है वह घनराशि 6,006 मिलियन डालर है तथा सब प्लानों में मिलाकर आज तक 9,433 मिलियन डालर मिला है । इस के सूद की सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री रवि राय : तैयार होकर आना चाहिये था ।

श्री मोरारजी देसाई : सूद के आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं, बाद में दूंगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पीछे रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपना यह वक्तव्य दिया था जिसमें यह कहा था कि उस देश की आर्थिक स्थिति की इस से ज्यादा दयनीय अवस्था और क्या हो सकती है जिस देश को सूद निबटाने के लिये भी बाहर से ऋण लेना पड़े तो मैं वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की अपनी दुर्बल आर्थिक स्थिति को सम्भालने के लिये क्या भविष्य में वित्त मंत्रालय ने कोई योजना बनाई है, अगर बनाई हो तो उस की रूपरेखा क्या है ?

श्री मोरारजी देसाई : शुरु में तो जो ऋण प्रदा करना है वह ऋण प्रदा करने के लिये

ऋण लेना पड़ेगा उस में तो कोई अस्वाभाविकता नहीं होती है। उस को भ्रदा करने के लिये आखिर में जो ऋण का उपयोग हम ने किया है उस में से जो आमदनी होगी उस में से ऋण भ्रदा किया जायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

हाल में कुछ ज्यादा तकलीफें व कठिनाइयां आर्थिक स्थिति में हैं इसी लिये हम ने उन को कहा है वर्ल्ड बैंक को और दूसरे देशों को कि इस ऋण के बाद फिर से लम्बी मुद्दत दी जाये तो ज्यादा आसानी से दिया जायेगा। उस के ऊपर वे लोग सोच रहे हैं। फँसला पूरा हुआ नहीं है।

श्री रामाबतार शर्मा : अभी जैसा आप ने फरमाया कि ऋण भ्रदा करने के लिये भी ऋण लिया जाये और भी तो उस में कोई बुरी बात नहीं है लेकिन हम लोगों का प्रश्न यह था कि क्या धीरे-धीरे विदेशी सहायता की राशि को कम करने का प्रस्ताव है या कोई सुझाव है, उस को भ्रदा करने का विचार सरकार के सम्मुख है या नहीं, इस का हम को कोई उत्तर नहीं मिल रहा है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं ने जो जवाब दिया माननीय सदस्यों ने उसे बराबर सुना नहीं, ऐसा मैं कह सकता हूँ या फिर मैं अपनी बात को पूरी तरह उन पर स्पष्ट नहीं कर पाया। मैंने यह कहा है कि शुरू में ऋण भ्रदा करने के लिये ऋण लेना जरूरी होता है, बाद में जरूरी नहीं पड़ता है और मैंने यह भी बताया था कि किस तरीके से इस ऋण को हम भ्रदा करेंगे।

श्री शिवकुमार शास्त्री : अभी वित्त मंत्री जी जब विदेश में गये थे तो वहाँ पर उन की घनराशि मांगने के लिये और सूद देने के लिये कि आसानी से आप दे सकें क्या इस विषय में कुछ बातचीत हुई थी और उस का क्या परिणाम निकला ?

श्री मोरारजी देसाई : यह भी अभी बता दिया था।

श्री शिव नारायण : देश में इस स्माल सेविंग्स स्कीम द्वारा अपने देशवासियों से कर्ज के लिये कुछ धन इकट्ठा करने का भी प्रोग्राम आप के पास है ?

श्री मोरारजी देसाई : स्माल सेविंग्स की स्कीम तो है और वह देश में चल रही है मगर सिर्फ स्माल सेविंग्स स्कीम से ही देश ऊँचा नहीं उठ जायेगा।

श्री रवि राय : क्या मंत्री महोदय का इस तरह ध्यान गया है कि जब-जब विदेशी सहायता बढ़ती जाती है, देश के विकास की दर घटती जाती है और इस के चलते हम बैंकरप्ट हो जाते हैं और जिसका कि नतीजा डीवैल्यूएशन है और जैसे कि अमरीका के कहने पर हम लोगों को अपने रुपये का मूल्य घटाना पड़ा तो उन का क्या इरादा है और कब तक यह विदेशी सहायता चलेगी ? क्या यह व्यक्तिगत देशों से जो विदेशी सहायता लेते हैं इस तरीके की उन के मन में कोई योजना है कि कोई एक वर्ल्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी या विश्व विकास संस्था बनेगी और उस के जरिये यह विदेशी सहायता लायें ताकि कोई व्यक्तिगत देशों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े या हमारा जो सार्वभौमिकत्व है उस को फिर हम खतरे में न डालें ?

श्री मोरारजी देसाई : वर्ल्ड बैंक से भी मिलता है। वहाँ से हमें ऋण मिलता है और अन्य देशों से भी ऋण मिलता है, मगर ऐसा ही एक संस्था के माफत सारा ऋण लेना यह सम्भव नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने विदेशी सहायता न लेने के लिये ऐड फौर नो ऐड (व्यवधान) आप अंग्रेजी की गुलामी मत करो।

MR. SPEAKER : Order, order. Go ahead with the question.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में जो डा० लोहिया साहब से वायदा किया था कि मैं इस के बाद में हिन्दी

में बोलने की कोशिश करूंगी तो मैं अब हिन्दी में ही यहां पर बोला करूंगी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह विदेशी सहायता न लेने के लिये, ऐड फौर नो ऐड यह जो प्रधान मंत्री ने बोला है तो उस स्वावलम्बी अवस्था के लिये हम को विदेशी सहायता आने से रूकावट क्यों है उस का कारण क्या है और उस को ठीक करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री मोरारजी देसाई : विदेशी सहायता हमारी आजादी को आजाद रख कर ही आती है उस को छोड़ कर नहीं आती है। उस में कोई ऐसी रूकावट नहीं है। कोई बाधा का सवाल नहीं है। आखिर को जिन लोगों के पास से हम यह लेते हैं जो हमें देते हैं उन की परिस्थिति पर हम आघार रखते हैं। हम किसी के बैंक में तो पैसा रखते नहीं हैं कि जब चाहें मांग लें और वह आशा और अपेक्षा भी हमें नहीं करनी चाहिये और उस में भी मुझे कोई शक नहीं है।

SHRI N. K. SOMANI : Is it not a fact that, generally, the lender and the donor countries are not satisfied with the utilisation of loans and aid given to us so far—that fact has been reiterated by the World Bank—which is one of the main reasons for the decline in foreign aid to us?

SHRI MORARJI DESAI : I do not agree with the presumption of the hon. Member.

SHRI S. R. DAMANI : During the last five years, our foreign debt has increased by Rs. 2,320 crores. During this year, there is an imbalance in our exports and imports. Our exports are lower than what we import. May I know what action Government is proposing to increase our exports to meet our liability of imports?

SHRI MORARJI DESAI : This has been stated from time to time by me and also by the Commerce Minister.

श्री रामसेवक यादव : जो यह विदेशी कर्ज और विदेशी मुद्रा का संकट और आर्थिक संकट मौजूद है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या अब भी विदेशों से

जो हम को कर्ज मिलता है, विदेशी मुद्रा मिलती है उस में हम खपत की चीजें अधिक मंगाते हैं या उस की मात्रा पहले से कम हुई है और अगर कम हुई है तो वह कितनी कम हुई है ?

श्री मोरारजी देसाई : खपत की चीजें तो हम अभी नहीं मंगाते हैं। वह कम से कम होंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जो अभी हालत है उस में मैं कहता हूँ कि हम बाहर से सिर्फ कच्चा माल मंगाते हैं वह कच्चा माल जो कि हमारे उद्योगों के लिये चाहिये और जो कि यहां हमारे देश में पैदा नहीं होता है वह ही मंगवाते हैं। कुछ मशीनरी मंगाते हैं और साथ में कुछ यंत्र सामग्री, पुर्जे आदि मंगाते हैं जिनकी कि हमें जरूरत होती है और जो कि यहां नहीं बनते हैं उन को मंगवाने के अलावा और कोई दूसरी चीज हम नहीं मंगवाते हैं।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : For every developing country foreign assistance and aid is also necessary. In the context of the statement just now made by the Deputy Prime Minister that we are trying to achieve self-sufficiency and not to depend any more on foreign aid, may I know whether this will influence the thinking of the Finance Ministry and also the Government of India in the formulation of the Plan to take adequate steps not to get more foreign aid as we have been doing before?

SHRI MORARJI DESAI : This is exactly the thinking on which the Planning Commission is working and the Government of India is also working. We hope that in the course of next 8 to 10 years, we will arrive at that position. पहले जो सवाल पूछा गया था उस का जवाब देते हुए ऐसी बात रह गयी थी और वह यह कि खपत की चीजों में हम बाहर से अनाज मंगवाते हैं।

श्री राम चरण : अभी जब वित्त मंत्री जी रीसेंटली दौरे पर गये थे तो क्या अपने सुपुत्र को भी अपने साथ ले गये थे और उस के लिये

फारेन एक्सचेंज किसी इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन ने दिया था या गवर्नमेंट का खर्च किया है ?

श्री मोरारजी देसाई : इसका जवाब देना हो तो मैं दे सकता हूँ ।

श्री तुलसीदास जाधव : जवाब जरूर दीजिये ताकि बात का खुलासा हो जाये ।

SHRI RANDHIR SINGH : What is this? This is very bad.... (Interruption)

श्री तुलसीदास जाधव : जरूर इसका जवाब दीजिये ।

SHRI MORARJI DESAI : May I say that a written question has been answered a few days ago and it is before the House?

श्री कंबर लाल गुप्त : मेरे सवाल के दो भाग हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस साल जो आपको विदेशी सहायता मिलने का अनुमान था क्या यह ठीक है कि उतनी सहायता आपको नहीं मिलने जा रही है और अगर नहीं मिल रही है तो कितनी कम मिलने जा रही है और उसको पूरा करने के लिये आप क्या इंतजाम करने जा रहे हैं ?

दूसरा भाग यह है कि कौन-कौन से देश ऐसे हैं जिन्होंने आपकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया है कि ब्याज वे ज्यादा देर तक लेंगे या नहीं लेंगे ? ऐसे कौन-कौन से देश हैं और कितना उसका असर पड़ेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : सारी तफसील इस वक्त बताना तो मुश्किल है । अगर आप चाहें तो मैं बाद में दे सकता हूँ । नहीं दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है । मैं दूंगा । लेकिन जो कर्ज कम मिलनेवाला है इस साल में उसकी वजह यह है कि यू० एस० में वहां के सेनेट ने जितना पैसा प्रेजीडेंट ने मांगा था उतना नहीं दिया है और उसको कम कर दिया है और इसी लिये वे कम देंगे ।

श्री कंबर लाल गुप्त : कितना कम देंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : यह तो बाद में मालूम होगा । उसका पूरा पता चला नहीं है । जब बतायेंगे तब पता चलेगा कि कितना कम होगा । दो सौ मिलियन डालर कम हो जायेगा या कितना कम हो जायेगा इसको मैं नहीं कह सकता हूँ । यह आंकड़ा बताना भी यह सजैस्ट करना होगा कि इतना कम हो जाये । इस लिये वह हितावह नहीं है । जितना कम मिलेगा उसके बगैर काम चलायेंगे और क्या करेंगे । दूसरों के पास मांगने जानेवाला मैं नहीं हूँ ।

श्री कंबर लाल गुप्त : ब्याज के बारे में भी मैंने पूछा था कि किन-किन देशों ने ब्याज कम किया है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने शुरू में कहा है कि तफसील चाहने हो तो मैं बाद में दे सकता हूँ । इस वक्त मेरे पास नहीं है । लेकिन इंग्लैंड ने जो पहले छः परसेंट ब्याज लेता था अब उन्होंने बदल दिया है । पच्चीस साल तक वह हमें कर्जा अदा करने का मौका देगा और पहले दस साल तक नहीं देना होगा और सूद बिल्कुल नहीं । यह तो इंग्लैंड ने किया है । जर्मनी ने भी कुछ तबदीली की है । ब्याज कम कर दिया है और मुद्दत बढ़ाई है । जापान ने भी कुछ कम किया है और मुद्दत बढ़ाई है । लेकिन सारी तफसील मैं नहीं दे सकता हूँ ।

श्री तुलसीदास जाधव : हर वह देश जो स्वतंत्र होता है वह दूसरे देशों से पैसा ले कर अपने यहां डिबेलपमेंट करता है और उसको पैसा लेना पड़ता है । हमारे देश में भी यही चलता है । मैं जानना चाहता हूँ कि दूसरे देशों का जो यह पीरियड है और जो दर्जा उन्होंने लिया है उसकी तुलना में हमारे देश के पीरियड और दर्जे के प्रोपोर्शन में क्या ज्यादा अन्तर है ? क्या दूसरे देशों की तुलना में कर्जा हम ने ज्यादा लिया है और पीरियड भी कर्जा लेने का हमारे यहां ज्यादा है ?

श्री मोरारजी देसाई : इस की तुलना करना तो मुश्किल है । लेकिन दुनिया में कोई

भो देश दूसरे देशों से मदद लिये बगैर बढ़ा हो नहीं है, बढ़ सकता नहीं है। हमारे देश ने दूसरे देशों से कोई ज्यादा लिया है, ऐसा मेरा मानना नहीं है।

SHRI INDRAJIT GUPTA : At the time when the rupee was devalued, when his predecessor was in office, one of the main arguments which was put forward before this House and before the country was that this measure would help to attract a greater volume of foreign assistance. I want to know from the hon. Finance Minister whether in the subsequent period this expectation has been realised or whether there has been a shortfall in the expectation. Does he consider devaluation to be an effective method of securing or inviting or attracting further foreign aid and if so, is there any truth in the rumours which are afloat that we are in for a second dose of devaluation? Or does he consider that it has failed to attract foreign assistance?

SHRI MORARJI DESAI : I do not think that devaluation was done in order to attract a larger dose of foreign aid; at least I was not in the Government then; I cannot say what was the reason for it. But the step of devaluation was taken, devaluation was adopted, for purposes of benefiting our economy which was not in a good condition at that time. But, as I have said earlier, the good effects that were supposed to follow from this have not turned out. Any measure can be devised and can fail. In my view that is no criticism of the method at all. There are two views in this matter. Even now there are two views in the matter. I have said before that as far as it lies within my power there will be no further devaluation.

SHRI VASUDEVAN NAIR : What does that mean ?

SHRI MORARJI DESAI : That means what it means. It does not mean anything else. It only means that I shall not do it. That is the meaning of it. It does not mean anything else. But in this matter, whatever one may say will always be open to some doubts by some people because they will say that it will be done after that. Whenever it is done.....

SHRI VASUDEVAN NAIR : If the World Bank asks you?

श्री रवि राय : दबाव में आकर करेंगे।

SHRI MORARJI DESAI : Yes, if I have to do it, I will resign and go. That is quite true. Therefore, there is no difficulty for me about it.

श्री जार्ज करनेन्डीस : चूँकि आपने अपनी किल्ली बता दी है इस वारते अब वे आपको हटाने का निश्चय करेंगे।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे लिये आपको निश्चित करने का मौका भी नहीं मिलेगा और न ज़रूरत होगी। मेरी एक मान्यता है। मेरे दूसरे जो साथी हैं उन की दूसरी मान्यता हो सकती है। इस बारे में दो रायें हो सकती हैं। इस लिये मेरे लिये दूसरों को दोष देना ठीक नहीं होगा। दोष मुझ में भी हो सकता है। मेरी बात भी गलत हो सकती है। उनकी बात सही हो सकती है। यह जो डिवैल्यूएशन हुआ है, इसके बारे में भी इकोनोमिस्ट्स की दो मान्यताएं हैं। अभी भी लोग कहते हैं कि वह ज़रूरी था। वे भी प्रामाणिक लोग हैं। यह मैं नहीं कह सकता हूँ कि वे प्रामाणिक लोग नहीं हैं और मैं हो इस बारे में जो कहता हूँ वह सही है। यह मैं नहीं कह सकता हूँ। इंग्लैंड ने भी पहले कहा था कि हम नहीं करेंगे। अब उन्होंने किया। क्या करोगे उसको। अलग-अलग दृष्टि बिन्दु होते हैं। जिन का जो दृष्टि बिन्दु होता है उसके अनुसार उसको फँसला करना होता है और बैसा फँसला वे कर लेते हैं। जिनका फँसला दूसरा होता है वे अपने दृष्टि बिन्दु से उस को ठीक समझते हैं। इसी लिये मैंने आपको यह बताया है। सब के लिये मैं नहीं बता सकता हूँ। सब गवर्नमेंट्स के लिये नहीं कह सकता हूँ। यह मेरा काम भी नहीं है, मेरा अधिकार भी नहीं है, हक भी नहीं है। इस लिये इस तरीके से बात करने से क्या फायदा ?

SHRI HEM BARUA : Sir, is it a fact that the Government had been forced to suspend or postpone the present Fourth

Five Year Plan due to the fact that adequate foreign assistance is not coming in spite of hon'ble Finance Minister's feelings and in spite of devaluation?

SHRI MORARJI DESAI : In the first place, I do not see how it arises from this. But I am prepared to say that the Fourth Five Year Plan is getting delayed, not because of any foreign exchange difficulty; it is getting delayed because of our own difficulties, of our own internal-resources difficulties and the conditions in the country. That is why it is getting delayed in formulation.

SHRI HEM BARUA : Our Five Year Plans mostly depend on foreign assistance.

SHRI R. K. AMIN : Has the hon'ble Finance Minister fixed any maximum limit to our foreign aid in terms of our national income and export capacity?

SHRI MORARJI DESAI : The maximum limit is the limit of our capacity to use it usefully.

SHRI BEDABRATA BARUA : It is a well known fact that the United States is generally allergic to public enterprises or enterprises run by the State. This is well known and it also came out in the case of steel plants. Will the hon'ble Finance Minister say whether there is any truth in the reports that the United States wants to advise us in regard to how we should run our public enterprises and how we should not enter into public enterprises and all that?

SHRI MORARJI DESAI : As far as I know, we have received no advice from the United States or any other Government whether to run our public enterprises or how to run them. If anybody gives that advice, well, anybody can give advice, but that advice will depend upon whether we consider that advice useful. If we consider that advice useful, then it becomes our idea; if it is not useful, we reject it outright.

श्री मधु लिमये : एक ओर तो सरकार अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर क्या यह बात सही है कि जो सहायता हम

लोगों को मिली है, उस का इस्तेमाल तत्काल और समय पर इस लिये नहीं होता है कि हमारी योजना का प्रारूप तैयार नहीं किया गया है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह बात तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जहां हमारी योजना तैयार नहीं है वहां हम ने कोई मदद नहीं मांगी है। मगर बाहर से जो मदद दी जाती है, वह सब सिर्फ योजना के लिये दी जाती है, ऐसी बात नहीं है। एक साल के लिये कितनी मदद देनी है, यह हिसाब कर के वे लोग मदद देते हैं। फिर अलग-अलग योजनाओं का भी हिसाब लगाया जाता है। लेकिन हर एक योजना एक साल में पूरी नहीं होती है। कुछ योजनाएं चार-पांच साल तक चलती हैं और कुछ छः साल तक चलती हैं। इस लिये जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ती है, वैसे-वैसे जो मदद मिलती है, उस का उपयोग होता जाता है। मान लीजिये कि एक योजना के लिये चार साल पहले हमें 200 करोड़ रुपये की मदद मिली और वह योजना छः साल तक पूरी होगी। तो हम हर साल उस 200 करोड़ रुपये में से आवश्यक मात्रा में पैसा लेते रहेंगे और बाकी पैसा पड़ा रहेगा इस लिए इस का मतलब यह नहीं है कि हम उस का उपयोग नहीं करते हैं और नहीं कर पा रहे हैं।

अन्तर्राज्यीय नदी विवाद

* 513. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अन्तर्राज्यीय नदी विवादों को निपटाने के लिये सरकार ने और क्या कार्यवाही की है; और

(ख) सरकार को इस कार्य में कितनी सफलता मिली है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख)। सिंचाई, बाढ़ और बिजली से सम्बद्ध कई एक